भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 998
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

राजस्थान में आंगनवाड़ी-सह-शिशु-गृह केंद्र

998. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विशेषकर झालावाड़ और बारां जिलों में कितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं और उनके वित्तपोषण की पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2029 तक देश भर में बाल-शिशु देखभाल और शिक्षा में वृद्धि तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में आंगनवाड़ी-सह-शिशु-गृह केंद्रों की स्थापना करने की सरकार की पहल का अनुमानित प्रभाव क्या है; और

(ग) राजस्थान के झालावाड़-बारां जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी-सह-शिशु-गृह केंद्रों के माध्यम से कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार, राजस्थान में कुल 62,276 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं, जिनमें से झालावाड़ और बारां ज़िलों में क्रमशः 1514 और 1689 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार राजस्थान को केंद्र और राज्य के बीच निम्नलिखित लागत-साझाकरण अनुपात पर अनुदान सहायता जारी करती है:

राज्य का नाम	एसएनपी में लागत साझाकरण अनुपात	एसएनपी को छोड़कर सभी घटकों में लागत साझाकरण अनुपात
राजस्थान	50:50	60:40

(ख) और (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की मिशन शक्ति के सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत पालना योजना शुरू की है।

उचित डे-केयर सेवाओं का अभाव अक्सर महिलाओं के लिए बाहर जाकर काम करने में बाधा बनता है। कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखरेख और सुरक्षा करने में आने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास - को प्राप्त करने हेतु पालना योजना के तहत डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखरेख संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखरेख और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखरेख सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखरेख की सेवाओं का विस्तार किया है, जिससे पूरे दिन बच्चों की देखरेख तथा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित होता है। पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक आयु) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। राजस्थान सहित पूरे देश में पालना के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं सभी माताओं को उपलब्ध कराई जाती है चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

15वें वित्त चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, पालना योजना के अंतर्गत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्थापित किए जाने हैं। अब तक, मंत्रालय द्वारा 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, कुल 14,599 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच को मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक, पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच की स्थापना और संचालन हेतु राजस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****